Achievements under Poverty Alleviation Programmes

870. SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state :

(a) the details of target set and achievements made under the major poverty alleviation programmes in Uttar Pradesh during the last three years; and

(b) the specific steps taken to ensure fulfilment of targets in the States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION) (SHRI VILAS BABURAO MUTTEMWAR): (a) Integrated Rural Development Programme (IRDP), Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Employment Assurances Scheme (EAS) are major poverty alleviation programmes being implemented by the Centre in various States including the State of Uttar Pradesh. A Statement showing the details of physical targets set and achievements made under these programmes in the States of Uttar Pradesh during the last three years is enclosed (*See* below).

(b) Various steps like monitoring of progress through periodical progress reports, organisation of review meetings of project Directors, remedial action based on the observation reports drawn by higher officers of the Central Government during their inspection visits under the Area Officers Scheme, State level coordination committee meetings and indepth study by way of Concurrent Evaluation etc. are taken to ensure fulfilment of targets.

Statement

Physical targets set and achieved during 1992-93, 1993-94 *and* 1994-95 *in respect of IRDP, JRY & EAS*

Programme	1992-93		1993-94		1994-95	
	Targets	Achievements	Targets	Achievements	Targets	Achievements
1	2	3	4	5	6	7
I.R.D.P.	369554	387961	416354	445403	325353	369725
J.R.Y.	1389.90	1496.29	1779.57	1791.16	1298.55	1395.94
E.A.S.	-	-	-	15.00	-	165.63

I.R.D.P. = Figures relate to Number of beneficiaries.

J.R.Y. & E.A.S. = Figures are in lakh mandays.

E.A.S. = This scheme started from 1993-94 and no targets are set under the scheme.

इस्पात का आयात

871. **श्री गोविन्दराम मिरी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात के आयात पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ख) क्या सरकार इस्पात का आयात कम करने का विचार रखती है;

(ग) इस्पात का आयात किस वर्ष तक बंद किए जाने की संभावना है;

(घ) इस समय प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया जा रहा है; और

(ङ) वर्ष 1995-96 के लिए इस्पात के आयात के संबंध में अनुमान क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित विक्रेय इस्पात का मूल्य निम्नानुसार था:-

वर्ष	(करोड़ रुपए)
1992-93	1640
1993-94	1603
1994-95	2536

(ख) और (ग) वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अनुसार इस्पात का आयात निर्बाध रूप से किया जा सकता है। तथापि, आयात की मात्रा आयातकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करती है ताकि मात्रा तथा गुणता दोनों की दृष्टि से घरेलू उपलब्धता को पूरा किया जा सके इस्पात का आयात घरेलू मांग, उपलब्धता और मूल्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। इस्पात की कुछ मात्रा का हमेशा आयात करने की आवश्यकता होगी विशेष रूप से उन श्रेणियों के, जिनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है और उनका देश में उत्पादन नहीं किया जाता।

(घ) पिछले तीन वर्षों में विक्रेय इस्पात का औसतन वार्षिक आयात 14.0 लाख टन है।

(ङ) अप्रैल-नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान आयात किए गए विक्रेय इस्पात का अनन्तिम मूल्य 1923 करोड़ रुपए है।

बिहार में सुनिश्चित रोजगार योजना

872. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या ग्रामीण और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत कितने प्रखंडों को लिया गया है तथा इस संबंध में स्वीकृत राशि एवं अदा की गई राशि का प्रखंड-वार ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत अभी उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत प्रखंडों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गये हैं और इस योजना के तहत कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग) (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है, तथापि, बिहार में 43 जिलों के 448 खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है। 1995-96 के दौरान जिलेवार रिलीज को संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तथा गहन जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पहले कवर किए गए सभी जिलों के अन्तर्गत कवर किए गये पुर्नगठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों में जैसे कि भूमि तथा जल संरक्षण, वन लगाना, कृषि बागवानी वन चरागाह लघु सिंचाई, सम्पर्क सड़कें, प्राथमिक पाठशाला तथा आंगनवाड़ी भवनों आदि को लिया जाता है।

विवरण

1995-96 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार को जिलेवार निधियों की रिलीज

क्रमांक	जिले	रिलीज निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	पटना	150.00
2.	नालन्दा	130.00
3.	भोजपुर	120.00
4.	रोहतास	170.00
5.	जहानाबाद	120.00
6.	मवादा	370.00
7.	पश्चिम चम्पारन	150.00
8.	पूर्वी चम्पारन	190.00
9.	सीतामढ़ी	500.00
10.	मधुबनी	310.00
11.	पूरनिया	90.00
12.	कठिडार	120.00
13.	खवाडिया	60.00
14.	गोड्डा	220.00
15.	साहिबगंज	380.00
16.	डुमका	400.00
17.	देवघर	210.00
18.	धनबाद	270.00
19.	गिरिडीह	270.00
20.	हजारीबाग	510.00
21.	पलामू	900.00
22.	लुहारडग्गा	110.00
23.	गुमला	430.00
24.	रांची	520.00
25.	पूर्वी सिंहभूम	780.00
26.	अररिया	110.00
27.	किशनगंज	60.00
28.	भबुआ	400.00
29.	बक्सर	60.00